

# Daily Current Affairs

Date : 13 February, 2026



## अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	राजस्थान में 'सेक्टरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज'
2.	राजस्थान में 15 नए औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा
3.	भगवान बिरसा मुंडा शोधपीठ - कोटा विश्वविद्यालय
4.	राइट ऑफ वे - अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार
5.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. हथकरघा एक्सपो-त्योहार 2.0 2. कौशिक पंवार - डॉ. अजीत सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार-2026 से सम्मानित 3. नरेन्द्र प्रताप सिंह - पीएम-युवा 3.0 के लिए चयनित 4. द आर्ट ऑफ इंडिया - 2026 - द टाइम्स ऑफ इंडिया 5. रींगस - सीकर रेलखंड दोहरीकरण 6. तनिष्क शर्मा
6.	राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड
7.	स्वामी दयानंद सरस्वती (1824-1883)
8.	वंदे मातरम
9.	आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)
10.	केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंध
11.	आर्कटिक सेंट्री (Arctic Sentry)
12.	दावोस कॉम्पैक्ट 2025
13.	युवा AI फॉर ऑल

--:1:--



## राजस्थान में 'सेक्टरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज'

### चर्चा में क्यों?

- राजस्थान सरकार के वित्त वर्ष 2026-27 के बजट का मुख्य विषय 'विकसित राजस्थान@2047' है। इस विज़न के प्रभावी क्रियान्वयन तथा शासन प्रणाली को अधिक समन्वित एवं परिणामोन्मुख बनाने के उद्देश्य से 'सेक्टरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज' का गठन किया गया है।

## Sectoral Group of Secretaries

Group 1: Rural Development and Agriculture.



Group 2: Infrastructure and Industry and Commerce.



Group 3: Resources.



Group 4: Social Welfare.



Group 5: Finance and Economy.



Group 6: Governance and Technology.



Group 7: Security-related departments.





## मुख्य बिन्दु:

- ज्ञातव्य है कि यह अवधारणा केन्द्रीय प्रशासन में सुशासन स्थापित करने में एक अत्यंत सफल मॉडल सिद्ध हुई है। इसी के मद्देनजर प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने 7 'सेक्टरल ग्रुप ऑफ सेक्रेट्रीज' के गठन के आदेश जारी किए।
- **उद्देश्य :** विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल और प्रभावी शासन सुनिश्चित करना।
- **'सेक्टरल ग्रुप ऑफ सेक्रेट्रीज' का प्रशासनिक विभाग :** आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार।
- इस मॉडल को राज्य में 'विकसित राजस्थान@2047' के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति, मध्यकालिक और दीर्घकालिक कार्य-योजना एवं मुख्य निष्पादन संकेतक (की परफोर्मिंग इंडिकेटर्स) बनाने, अंतर-विभागीय मुद्दों के निस्तारण, बजट घोषणाओं व राजस्थान संकल्प पत्र-2023, फ्लैगशिप योजनाओं तथा समान उद्देश्यों वाली योजनाओं के युक्तिकरण एवं विलय की समीक्षा करने के लिए अपनाया जा रहा है।

ग्रुप ऑफ सेक्रेट्रीज को संबंधित विभाग के सचिव के नेतृत्व में मुख्य रूप से 7 समूहों में बाँटा गया है:

- **समूह 1 :** ग्रामीण विकास और कृषि।
- **समूह 2 :** अवसंरचना और उद्योग एवं वाणिज्य।
- **समूह 3 :** संसाधन।
- **समूह 4 :** समाज कल्याण।
- **समूह 5 :** वित्त एवं अर्थव्यवस्था।
- **समूह 6 :** शासन एवं प्रौद्योगिकी।
- **समूह 7 :** सुरक्षा से जुड़े विभाग।

## कार्य:

- ये समूह 'विकसित राजस्थान@2047' हेतु रणनीति, कार्य-योजना एवं मुख्य निष्पादन संकेतक (KPI) तैयार करेंगे ताकि इसके लक्ष्यों को बेहतर समन्वय से निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जा सके।
- प्रत्येक समूह के लिए एक संयोजक और एक सह-संयोजक बनाए गए हैं, जो समूह के सदस्यों के साथ अपने स्तर पर बैठकें करेंगे और प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों सहित कार्य योजना का सारांश तैयार करेंगे।

## राजस्थान में 15 नए औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा



### चर्चा में क्यों?

- राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा बजट 2026-27 में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्रदेश में 15 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की गई।



### मुख्य बिन्दु:

#### प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र:

क्रम संख्या	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	जिला
1.	फागी	जयपुर
2.	चौमूं	
3.	मौजमाबाद	
4.	दूदू	
5.	भिनाय	अजमेर
6.	परबतसर	डीडवाना-कुचामन
7.	निवाई	टोंक
8.	आऊ	फलौदी

--:4::--

# Daily Current Affairs

Date : 13 February, 2026



9.	फलौदी	
10.	मुण्डावर	खैरथल-तिजारा
11.	नीमराणा	कोटपूतली-बहरोड़
12.	रामगंजमण्डी	कोटा
13.	लाडपुरा	
14.	बिजौली	धौलपुर
15.	दातारामगढ़	सीकर

## फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

### राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RIICO)

- RIICO एक सरकारी उपक्रम है, जिसकी स्थापना 28 मार्च, 1969 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत राजस्थान राज्य औद्योगिक और खनिज विकास निगम (RSIMDC) के रूप में की गई थी।
- 1 जनवरी, 1980 को इसे दो अलग-अलग इकाइयों में विभाजित कर दिया गया:
  - RIICO** - राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
  - RSMDC** - राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम।

### मुख्य कार्य:

- RIICO ने राजस्थान में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- यह राज्य के विभिन्न हिस्सों में औद्योगिक क्षेत्र (Industrial Areas) का विकास करता है।
- एक वित्तीय संस्था के रूप में यह छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराता है।
- उद्योगों को वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन और बुनियादी ढाँचे के विकास में सहयोग प्रदान करता है।
- वर्ष 2021-22 में, RIICO को COSIDICI द्वारा देश की सबसे श्रेष्ठ SIIDC (राज्य औद्योगिक विकास निगम) के रूप में सम्मानित किया गया।
- राज्य भर में 33 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं, जो औद्योगिक क्षेत्रों के कुशल संचालन और प्रबंधन को सुनिश्चित करते हैं।

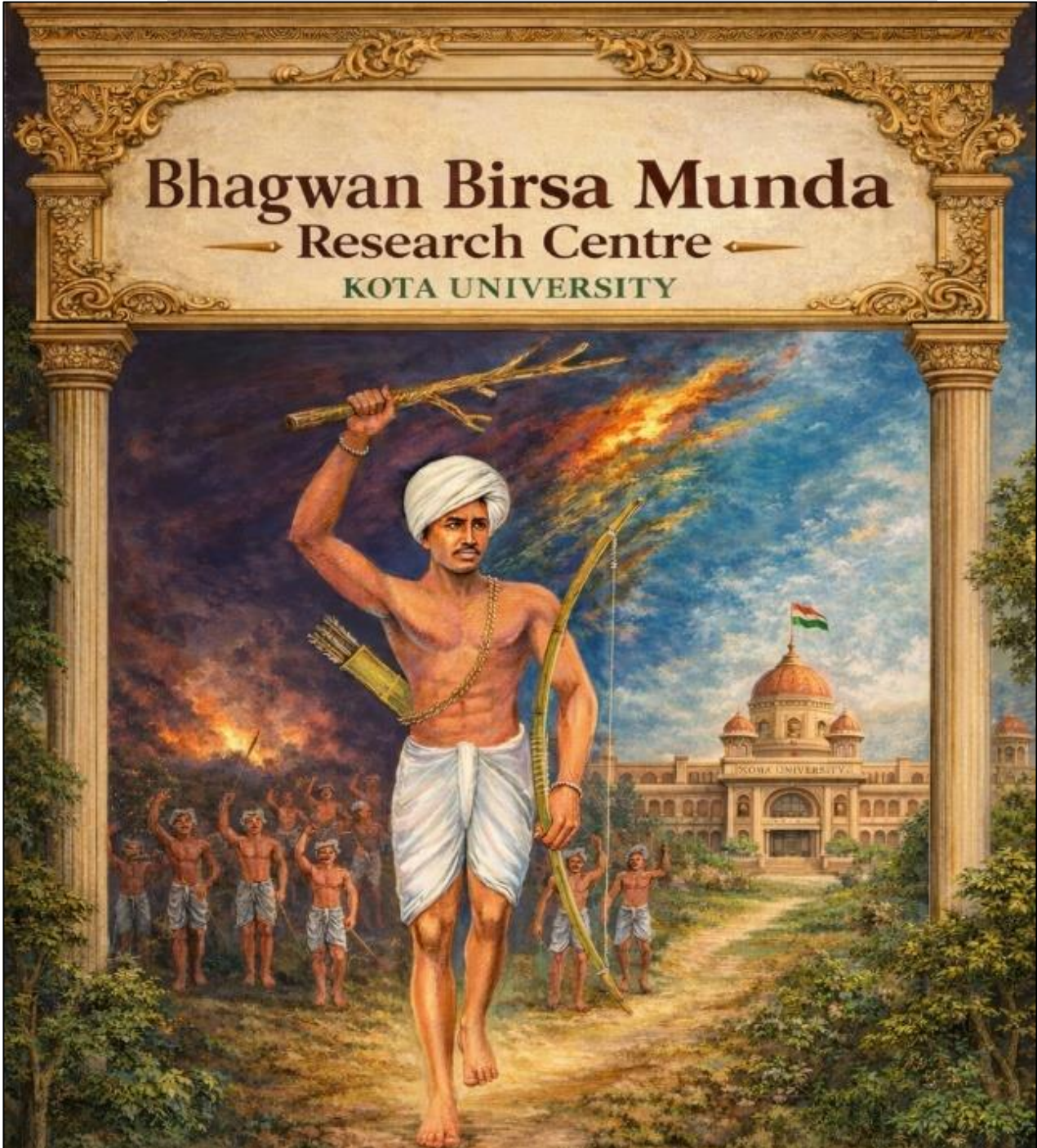
--5--

## भगवान बिरसा मुंडा शोधपीठ - कोटा विश्वविद्यालय



### चर्चा में क्यों?

- राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा बजट 2026-27 में कोटा विश्वविद्यालय में भगवान बिरसा मुंडा शोधपीठ की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई।



--:6:--



## मुख्य बिन्दु:

- **उद्देश्य :** जनजातीय नायक बिरसा मुंडा के जीवन, दर्शन, और उनके द्वारा किए गए आदिवासी प्रतिरोध व सामाजिक सुधारों पर गहन शोध करना।
- देश भर में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है वहीं राजस्थान में इस दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 13.5 प्रतिशत हिस्सा आदिवासी जनजाति (अनुसूचित जनजाति) का है।
- राज्य में मीणा, भील, गरासिया और सहरिया सबसे बड़े आदिवासी समुदाय है।

## फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

### बिरसा मुंडा के बारे में:

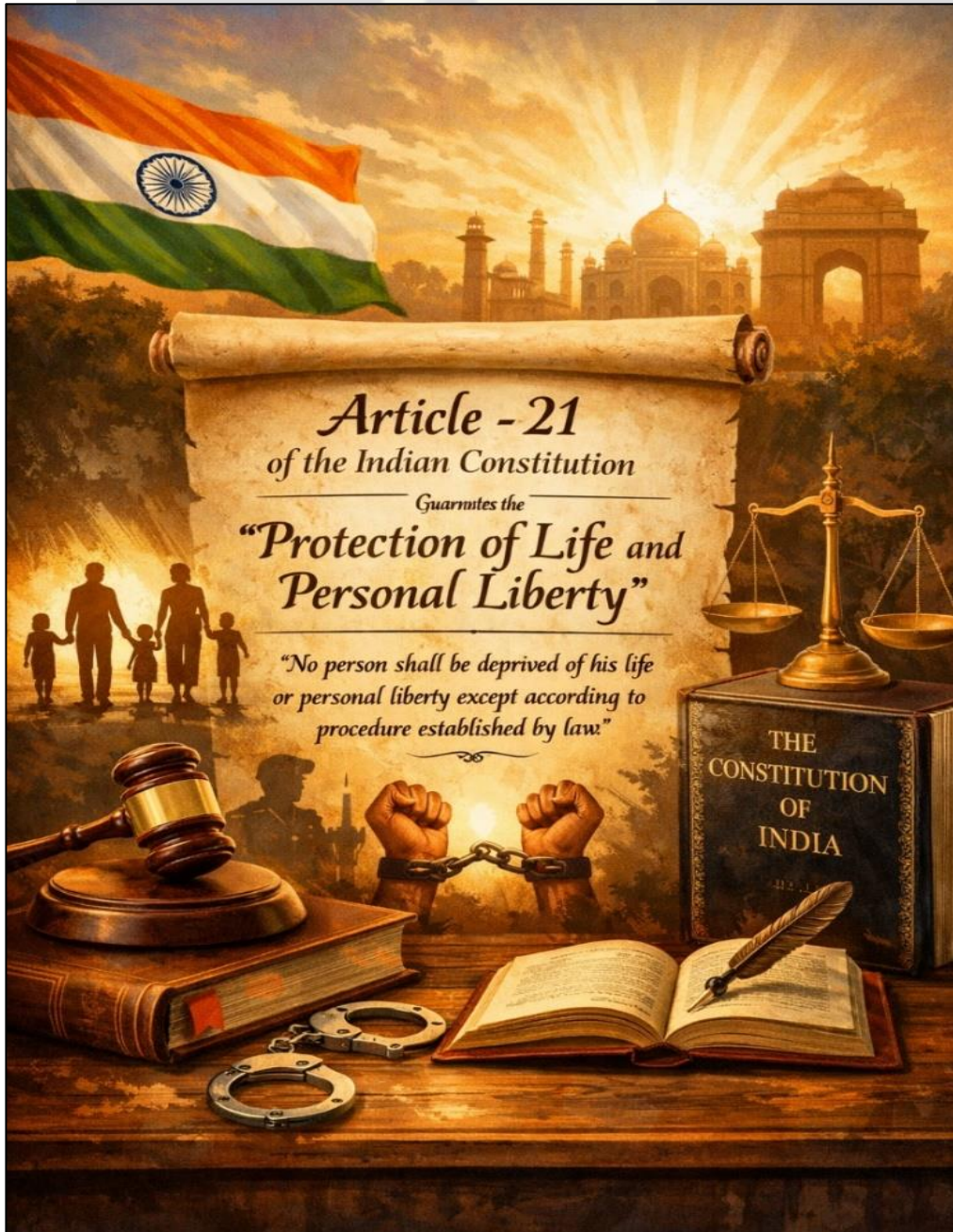
- बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर, 1875 को छोटा नागपुर पठार क्षेत्र (वर्तमान झारखंड का खूंटी जिला) में मुंडा जनजाति में हुआ था।
- बिरसा मुंडा एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और 'उलगुलान' (क्रांति) का आह्वान करते हुए ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। आदिवासियों ने उन्हें 'भगवान' की उपाधि दी। उन्हें 'धरती आब्बा, जिसका अर्थ है 'पृथ्वी का पिता' के नाम से भी जाना जाता है।
- आदिवासियों के खिलाफ शोषण एवं भेदभाव के विरुद्ध उनके संघर्ष के कारण ही वर्ष 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम (Chhotanagpur Tenancy Act) पारित किया गया, जिसने आदिवासी लोगों से गैर-आदिवासियों में भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित कर दिया।

## राइट ऑफ वे - अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार



### चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दो महीने के भीतर राज्य भर में राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत आने वाले सभी अतिक्रमणों को हटाने या स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है।



--8--

## मुख्य बिन्दु:

- उच्च न्यायालय ने माना कि सड़कों पर सुरक्षित आवाजाही संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है और न्यायालय ने इसे 'राइट ऑफ वे' के रूप में परिभाषित किया है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21** : किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।
- **न्यायिक व्याख्या** : सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर इसकी व्याख्या को व्यापक बनाया है। अब जीवन का अर्थ केवल 'जीवित रहना' नहीं बल्कि 'मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीना' है।
- **ए.के. गोपालन वाद (1950)** : सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की संकुचित व्याख्या की थी।
- **मेनका गाँधी वाद (1978)** : इस ऐतिहासिक मामले में कोर्ट ने 'विधि की उचित प्रक्रिया' के सिद्धांत को अपनाया, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दायरा बढ़ गया।
- **नोट** : सर्वोच्च न्यायालय ने पुट्टास्वामी वाद (2017) में 'निजता का अधिकार' को भी अनुच्छेद-21 के तहत मौलिक अधिकार माना।

## ✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p><b>हथकरघा एक्सपो-त्योहार 2.0</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>11 से 17 फरवरी, 2026 तक जयपुर में हथकरघा एक्सपो 'त्योहार-2.0' का आयोजन किया जाएगा।</li><li><b>उद्देश्य</b> : बुनकरों को एक साझा मंच प्रदान करना और भारतीय सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना।</li><li><b>आयोजन स्थल</b> : बिड़ला ऑडिटोरियम, जयपुर।</li><li><b>आयोजक</b> : केन्द्रीय वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत बुनकर सेवा केंद्र, जयपुर।</li><li>बुनकर सेवा केंद्र, जयपुर केन्द्रीय वस्त्र मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है। यह कार्यालय राजस्थान में हथकरघा क्षेत्र के बुनकरों के विकास के लिए समर्पित है।</li></ul>
2.	<p><b>कौशिक पंवार - डॉ. अजीत सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार-2026 से सम्मानित</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>उदयपुर के शारीरिक शिक्षक कौशिक पंवार को शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉ. अजीत सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार-2026 से सम्मानित किया गया।</li><li><b>आयोजन</b> : यह पुरस्कार भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय तथा फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया (PEFI) द्वारा नई दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया।</li><li><b>राजस्थान से एकमात्र चयन</b> : देशभर से विभिन्न श्रेणियों में चयनित 30 शारीरिक शिक्षकों में से कौशिक पंवार राजस्थान के एकमात्र शिक्षक थे जिन्हें इस सम्मान के लिए चुना गया।</li></ul>

3.	<p><b>नरेन्द्र प्रताप सिंह - पीएम-युवा 3.0 के लिए चयनित</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर के छात्र नरेन्द्र प्रताप सिंह का चयन पीएम-युवा 3.0 (PM-YUVA 3.0) मेंटरशिप योजना के लिए हुआ।</li><li><b>संस्कृत विषय के एकमात्र लेखक</b> : नरेन्द्र प्रताप सिंह संस्कृत भाषा की श्रेणी में इस योजना के लिए चुने गए देशभर के एकमात्र युवा लेखक हैं।</li><li>भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना (पीएम-युवा 3.0) का उद्देश्य 30 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों को भारत की संस्कृति, विरासत, भारतीय ज्ञान परंपरा, राष्ट्र निर्माण में भारतीय प्रवासी तथा आधुनिक भारत (1950-2025) के निर्माताओं जैसे विषयों पर लेखन हेतु प्रोत्साहित करना है।</li><li>इस योजना के तहत चयनित लेखक को प्रतिमाह 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति (कुल 3 लाख रुपये), पांडुलिपि का प्रकाशन तथा 10 प्रतिशत रॉयल्टी प्रदान की जाती है।</li></ul>
4.	<p><b>द आर्ट ऑफ इंडिया - 2026 - द टाइम्स ऑफ इंडिया</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>द टाइम्स ऑफ इंडिया और स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा संयुक्त रूप से 14 से 22 फरवरी, 2026 तक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC), जयपुर में 'द आर्ट ऑफ इंडिया' का पाँचवाँ संस्करण आयोजित किया जा रहा है।</li><li><b>उद्घाटन</b> - उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा।</li></ul>
5.	<p><b>रींगस - सीकर रेलखंड दोहरीकरण</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>हाल ही में रेल मंत्रालय द्वारा रींगस और सीकर के बीच 50 किलोमीटर रेलखंड के दोहरीकरण के लिए ₹470.34 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई।</li><li>रींगस से सीकर रेलखंड के दोहरीकरण से धार्मिक पर्यटन (विशेष रूप से खाटूश्याम) को बढ़ावा मिलेगा।</li></ul>
6.	<p><b>तनिष्क शर्मा</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>उत्तर प्रदेश के मोदीनगर में आयोजित यूथ जूनियर एवं सीनियर वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में राजस्थान के तनिष्क शर्मा ने 94 किलो भार वर्ग में 127 किलो स्नैच और 146 किलो क्लीन एंड जर्क (कुल 273 किलो) उठाकर कांस्य पदक जीता।</li></ul>

## राष्ट्रीय परिदृश्य

### राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड

#### चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे किए।

### National Medicinal Plants Board(NMPB)

- India is one of the richest countries in the world in terms of biodiversity, has 15 agro-climatic zones. Out of the 17000-18000 species of flowering plants, more than 7000 are estimated to have medicinal usage in folk and documented systems of medicine like Ayurveda, Unani, Siddha & Homoeopathy (AYUSH System of Medicine).
- The Government of India has set up National Medicinal Plants Board (NMPB) on 24th November 2000. Currently the board is working as a section of Ministry of AYUSH (Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha & Homoeopathy), Government of India.
- The primary mandate of NMPB is to develop an appropriate mechanism for coordination between various ministries/ departments/ organizations in India and implements support policies/programs for overall (conservation, cultivation, trade and export) growth of medicinal plants sector both at the Central /State and International level

#### मुख्य बिन्दु:

#### राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (NMPB):

- मुख्यालय: नई दिल्ली
- स्थापना: वर्ष 2000 में भारत सरकार के एक संकल्प के माध्यम से स्थापित।
- मंत्रालय: केंद्रीय आयुष मंत्रालय।
- अध्यक्ष: केंद्रीय आयुष मंत्री।
- औषधीय पादपों से संबंधित पहलें:
- ई-चरक पोर्टल: विभिन्न हितधारकों के बीच सूचना के आदान-प्रदान हेतु एक ऑनलाइन बाजार तंत्र।
- औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और संधारणीय प्रबंधन पर केंद्रीय क्षेत्रक योजना।

## इतिहास एवं संस्कृति

### स्वामी दयानंद सरस्वती (1824-1883)

#### चर्चा में क्यों?

- हाल ही में समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती को उनकी जयंती (12 फरवरी) पर स्मरण किया गया।

#### मुख्य बिन्दु:

- जन्म:** गुजरात
- उन्होंने वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी।
- उन्होंने बाल विवाह और विधवाओं पर थोपी जाने वाली कठोर प्रथाओं जैसी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया।
- वे ऐसी शिक्षा प्रणाली के पक्ष में थे जो व्याकरण, दर्शन, वेदों, विज्ञान, चिकित्सा, संगीत और कला पर जोर दे।
- उन्होंने एक ऐसी शासन व्यवस्था की कल्पना की जो विकेंद्रीकरण का प्रतीक हो।
- महत्त्वपूर्ण साहित्यिक कृति:** सत्यार्थ प्रकाश।
- आध्यात्मिक:** उन्होंने 'त्रैतवाद' की वैदिक अवधारणा प्रस्तुत की।

## वंदे मातरम्

### चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में 'वंदे मातरम्' के गायन से संबंधित औपचारिक प्रोटोकॉल को स्पष्ट करते हुए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

### मुख्य बिन्दु:

#### दिशा-निर्देश के मुख्य बिंदु:

- जब वंदे मातरम् और राष्ट्रगान, दोनों प्रस्तुत किए जाएँ, तो वंदे मातरम् पहले गाया जाएगा।
- वंदे मातरम् गायन के समय श्रोताओं को सावधान की मुद्रा में खड़ा रहना होगा।
- हालांकि, यदि यह किसी फिल्म या वृत्तचित्र का हिस्सा हो, तो सावधान की मुद्रा अनिवार्य नहीं होगी।

#### वंदे मातरम्:

- **इतिहास:** संस्कृत भाषा में (बंगाली लिपि में) बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित।
- पहली बार 1875 में साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में प्रकाशित, फिर वर्ष 1882 में उपन्यास आनंदमठ में प्रकाशित।
- इसे वर्ष 1950 में संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्र गीत के रूप में अपनाया गया।
- 24 जनवरी, 1950 को यह घोषणा की गई कि वंदे मातरम् को राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' के समान दर्जा प्राप्त होगा।
- वर्ष 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रवींद्रनाथ टैगोर ने मंच पर वंदे मातरम् गाया। यह पहला अवसर था जब यह गीत सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर गाया गया।

In which of the following, 'Vande Mataram' was adopted as a slogan for agitation?

- (A) Quit India Movement, 1942
- (B) Non-Cooperation Movement, 1922
- (C) Partition of Bengal, 1905
- (D) Revolt of 1857

## आर्थिक घटनाक्रम

### आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)

#### चर्चा में क्यों?

- PLFS जनसंख्या की रोजगार-बेरोजगारी की स्थिति पर डेटा का प्राथमिक स्रोत है।

#### मुख्य बिन्दु:

- इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा संचालित किया जाता है।

### श्रम बाजार की प्रमुख शब्दावलियां



#### श्रम बल भागीदारी दर (LFPR):

यह कुल आबादी में श्रम बल में शामिल व्यक्तियों का प्रतिशत है। इसमें कार्यरत या काम की तलाश में लगे लोग या काम करने के लिए उपलब्ध लोग शामिल हैं।



#### श्रमिक-जनसंख्या अनुपात (WPR):

WPR को कुल आबादी में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है।



#### बेरोजगारी दर (UR):

इसे श्रम बल में शामिल कुल लोगों में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है।



#### वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS):

कार्य गतिविधि का निर्धारण सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के सात दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर किया जाता है।

### अक्टूबर-दिसंबर 2025 के दौरान PLFS के मुख्य निष्कर्ष

- श्रम बल भागीदारी दर (LFPR): 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में समग्र LFPR बढ़कर 55.8% हो गई है।

# Daily Current Affairs

Date : 13 February, 2026



- **महिला LFPR में वृद्धि:** 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की समग्र LFPR में बढ़त देखी गई, जो बढ़कर 34.9% हो गई।
- **कार्यबल में वृद्धि:** 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए समग्र कामगार जनसंख्या अनुपात (WPR) बढ़कर 53.1% हो गया।
- **ग्रामीण WPR:** 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए ग्रामीण WPR ने पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों में निरंतर वृद्धि दर्ज की है।
- **बेरोजगारी दर (UR):** इसमें ग्रामीण (4%) और शहरी (6.7%) दोनों क्षेत्रों में गिरावट आई है।
- **स्वरोजगार:** ग्रामीण (63.2%) और शहरी (39.7%) दोनों क्षेत्रों में स्वरोजगार में वृद्धि हुई है।
- **कार्यबल का संकेंद्रण:** ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश कामगार कृषि क्षेत्रक (58.5%) में लगे हुए हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में तृतीयक (सेवा) क्षेत्रक स्थिर रहा, जहां 61.9% कामगार कार्यरत हैं।

-:17:-

## केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंध

### चर्चा में क्यों?

- वित्त मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार ने विभाज्य निधि का 41% हिस्सा राज्यों को हस्तांतरित कर दिया है।

# केंद्र - राज्य सम्बन्ध

## विधायी सम्बन्ध

Article – 245 to 255

भाग – 11

## प्रशासनिक सम्बन्ध

Article – 256 to 263

भाग – 11

## वित्त सम्बन्ध

Article – 264 to 293

भाग – 12

### मुख्य बिन्दु:

#### कर हस्तांतरण क्या है?

- कर हस्तांतरण से तात्पर्य केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच कर राजस्व के वितरण से है।
- वित्त आयोग यह तय करता है कि केंद्र के शुद्ध कर राजस्व का कितना अनुपात राज्यों को समग्र रूप से जाता है (ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण) और राज्यों के लिए यह हिस्सा विभिन्न राज्यों के बीच कैसे वितरित किया जाता है (क्षैतिज हस्तांतरण)।
- 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि विभाज्य करों के कोष का 41% हिस्सा राज्यों को हस्तांतरित किया जाए।

- राज्यों के बीच धन का क्षैतिज हस्तांतरण आमतौर पर आयोग द्वारा बनाए गए एक सूत्र के आधार पर तय किया जाता है, जिसमें राज्य की जनसंख्या, प्रजनन स्तर, आय स्तर, भूगोल आदि को ध्यान में रखा जाता है।
- केंद्र सरकार कुछ ऐसी योजनाओं के लिए अतिरिक्त अनुदान देकर राज्यों की सहायता भी करती है, जिनका वित्तपोषण केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

## केंद्र और राज्यों के बीच टकराव

- कर राजस्व के बंटवारे के मुद्दे पर केंद्र और राज्यों के बीच मतभेद बना हुआ है।
- केंद्र सरकार आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) जैसे प्रमुख करों का संग्रह करती है, जबकि राज्य सरकारें मुख्य रूप से शराब और ईंधन जैसी वस्तुओं की बिक्री से एकत्रित करों पर निर्भर करती हैं, जो जीएसटी के दायरे से बाहर हैं।
- इसके चलते यह शिकायतें सामने आई हैं कि केंद्र ने राज्यों की कर संग्रह करने की शक्ति को कम कर दिया है और वह राज्यों को उनकी जिम्मेदारियों के अनुरूप पर्याप्त धनराशि नहीं देता है।

## राज्यों की प्रमुख मांगें

- **अधिक धनराशि की मांग:** राज्य सरकारें तर्क दे रही हैं कि उन्हें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित धनराशि से अधिक धनराशि मिलनी चाहिए। राज्यों की जिम्मेदारियां अधिक हैं, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पुलिस सेवाएं शामिल हैं।
- **विभाज्य पूल संबंधी चिंताएँ:** उपकर और अधिभार, जो राज्यों के साथ साझा नहीं किए जाते हैं, केंद्र के कर राजस्व का 28% तक हो सकते हैं, जिससे साझा करने योग्य राजस्व आधार का आकार कम हो जाता है।
- **वित्त आयोग की आलोचना:** केंद्र सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति में निभाई गई भूमिका के कारण वित्त आयोग पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो सकता है, जिससे संभावित राजनीतिक प्रभाव पड़ सकता है।

# Daily Current Affairs

Date : 13 February, 2026



## केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 202 से 206:** राज्यों के वित्तीय प्रशासन से संबंधित हैं, जिनमें उनके बजट, व्यय, उधार लेने और कराधान शक्तियों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
- **अनुच्छेद 268 से 272:** संघ और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं।
- **अनुच्छेद 280:** प्रत्येक पांच वर्ष में (या राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट अनुसार) वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान।
- केंद्र सरकार वित्त आयोग द्वारा दिए गए सुझावों को लागू करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है।
- **अनुच्छेद 282:** केंद्र सरकार को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की अनुमति देता है।

--:20:--

## अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

### आर्कटिक सेंट्री (Arctic Sentry)

#### चर्चा में क्यों?

- उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) ने आर्कटिक में सुरक्षा बढ़ाने के लिए 'आर्कटिक सेंट्री' नामक एक नया मिशन शुरू किया है।



# Daily Current Affairs

Date : 13 February, 2026

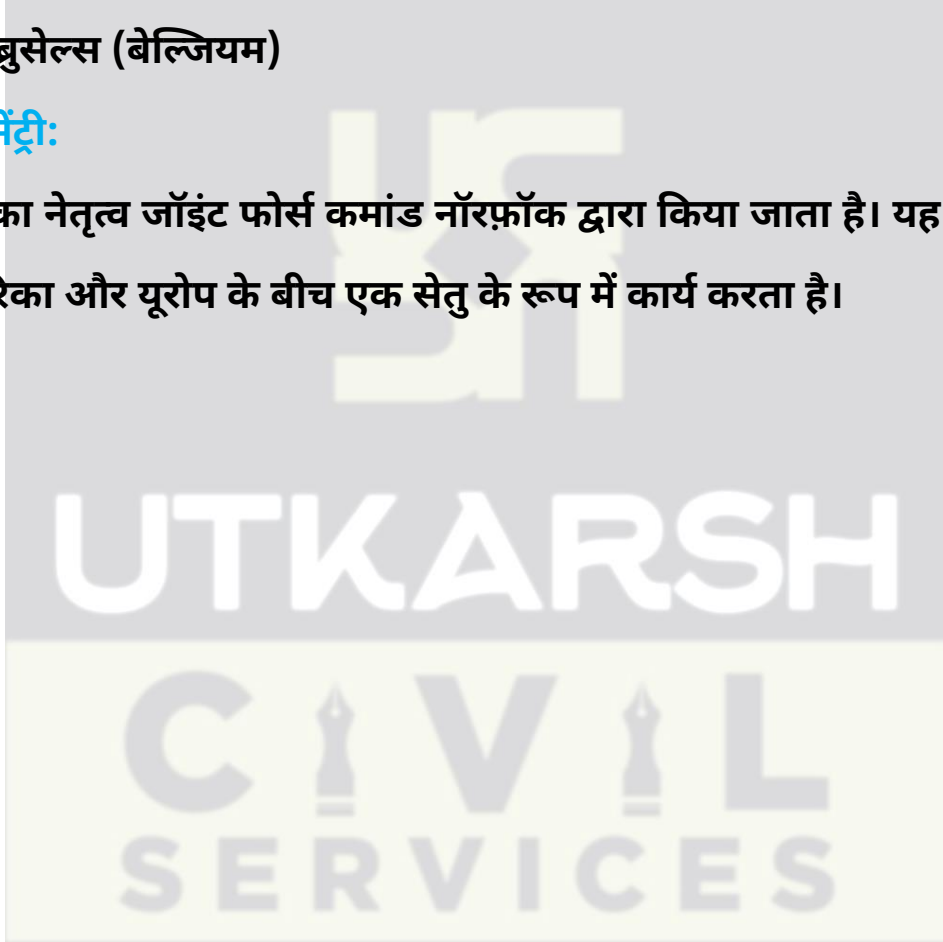


## मुख्य बिन्दु:

- NATO एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना वर्ष 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर के बाद की गई थी।
- वर्तमान में इसमें 32 सदस्य हैं।
- **मुख्यालय:** ब्रुसेल्स (बेल्जियम)

## आर्कटिक सेंट्री:

- **नेतृत्व:** इसका नेतृत्व जॉइंट फोर्स कमांड नॉरफ़ॉक द्वारा किया जाता है। यह नाटो के लिए उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है।



-:22:-

## विज्ञान प्रौद्योगिकी

### दावोस कॉम्पैक्ट 2025



#### चर्चा में क्यों?

- विश्व आर्थिक मंच ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर दावोस कॉम्पैक्ट 2025 लॉन्च किया। यह कॉम्पैक्ट, 'एकीकृत AMR प्रतिक्रिया गठबंधन' द्वारा समर्थित है।

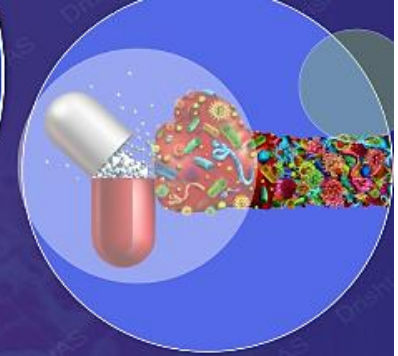


#### मुख्य बिन्दु:

- उद्देश्य:** सार्वजनिक और निजी दोनों स्रोतों से स्थायी वित्त-पोषण प्राप्त करना है, ताकि वैश्विक स्तर पर AMR से होने वाली मौतों को कम किया जा सके।

## (AntiMicrobial Resistance-AMR)

सूक्ष्मजीवों में रोगाणुरोधी दवाओं के प्रभाव का विरोध करने की क्षमता



### AMR में वृद्धि के कारण

- संक्रमण नियंत्रण/स्वच्छता की खराब स्थिति
- एंटीबायोटिक दवाओं का अति प्रयोग
- सूक्ष्मजीवों का आनुवंशिक उत्पत्ति
- नई रोगाणुरोधी दवाओं के अनुसंधान एवं विकास में निवेश का अभाव

AMR विकसित करने वाले सूक्ष्मजीवों को 'सुपरबग' कहा जाता है

### AMR के प्रभाव

- ↑ संक्रमण फैलने का खतरा
- संक्रमण को इलाज को कठिन बना देता है; लंबे समय तक चलने वाली बीमारी
- ↑ स्वास्थ्य सेवाओं की लागत

### उदाहरण

- K निमोनिया में AMR के कारण कार्बापेनेम (Carbapenem) एंटीबायोटिक्स प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं
- AMR माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, रिफैम्पिसिन-प्रतिरोधी टीबी (RR-टीबी) का कारण बनता है
- दवा प्रतिरोधी HIV (HIVDR) एंटीरेट्रोवाइरल (ARV) दवाओं को अप्रभावी बना रहा है

### WHO द्वारा मान्यता

- AMR की पहचान वैश्विक स्वास्थ्य के लिये शीर्ष 10 खतरों में से एक के रूप में
- वर्ष 2015 में GLASS (ग्लोबल एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस एंड यूज सर्विलांस सिस्टम) लॉन्च किया गया

### AMR के खिलाफ भारत की पहलें

- टीबी, वेक्टर जनित रोग, एड्स आदि का कारण बनने वाले रोगाणुओं में AMR की निगरानी।
- वन हेल्थ के दृष्टिकोण के साथ AMR पर राष्ट्रीय कार्य योजना (2017)
- ICMR द्वारा एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम

न्यू देल्ही मेटालो-बीटा-लैक्टामेज़-1 (NDM-1) एक जीवाणु एंजाइम है, जिसका उद्भव भारत से हुआ है, यह सभी मौजूदा  $\beta$ -लैक्टम एंटीबायोटिक्स को निष्क्रिय कर देता है

## रोगाणुरोधी प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance: AMR)

- यह तब होता है, जब जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीवी रोगाणुरोधी दवाओं (जैसे-एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीफंगल आदि) का प्रतिरोध करने के लिए तंत्र विकसित कर लेते हैं। इससे ये दवाएं अप्रभावी हो जाती हैं।
- यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो समय के साथ रोगजनकों में आनुवंशिक परिवर्तनों के माध्यम से होती है।
- हालांकि, मानव-जनित गतिविधियों, मुख्य रूप से रोगाणुरोधी दवाओं के दुरुपयोग एवं अत्यधिक उपयोग के कारण इसके प्रसार में तेजी आई है।
- **भारत में स्थिति:** भारत में प्रतिवर्ष प्रतिरोधी संक्रमणों के कारण लगभग 6 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है।

UTKARSH

CIVIL  
SERVICES

## युवा AI फॉर ऑल



### चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने "युवा AI फॉर ऑल" कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल रथ का शुभारंभ किया। इसे अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी सोसायटी के सहयोग से शुरू किया गया।



### मुख्य बिन्दु:

- कौशल रथ मोबाइल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जागरूकता पहल है। इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर AI शिक्षा का लोकतंत्रीकरण करना है।

Ministry of Electronics and Information Technology | Digital India | INDI/AI | AI IMPACT SUMMIT

## YUVA AI FOR ALL

A **free**, beginner-friendly **AI course** launched by the Government of India to help every citizen understand Artificial Intelligence

Real Indian use cases

4.5 hrs of simple learning

Self-paced, anytime

Ethical & responsible AI

Govt. of India certificate

--:25:--

# Daily Current Affairs

Date : 13 February, 2026



## युवा AI फॉर ऑल:

- यह निःशुल्क, 4.5 घंटे का स्व-गति वाला राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है। इसका लक्ष्य AI को प्रत्येक भारतीय के लिए सुलभ और समझने योग्य बनाना है।
- यह फ्यूचरस्किल्स प्राइम, iGOT कर्मयोगी सहित अन्य प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है।
- यह इंडिया AI मिशन का हिस्सा है।
- इंडिया AI मिशन को मार्च 2024 में स्वीकृति दी गई थी।



--:26:--